

UGC Approved, Journal No. 49321
Impact Factor : 6.125



ISSN : 0976-6650

शोध दृष्टि

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 14, No. 10

October, 2023

PEER REVIEWED JOURNAL

५	उच्च शिक्षा में दलित छात्राओं की भागीदारी : उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के विशेष सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन रमा देवी एवं डॉ० रामजी प्रसाद	73-79
५	शिक्षक शिक्षा में मूल्य शिक्षा की प्रासंगिकता प्रेम प्रकाश विजय	80-82
५	हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में चीन की संतुलनकारी भूमिका में क्वाड शिवम सिंह एवं डॉ० जयकुमार मिश्र	83-86
५	आचार्यकुन्तकाभिमतकाव्यस्वरूपविमर्शः बरषा पाटगिरि	87-90
५	आधुनिक शिक्षण कौशल में विभिन्न एप्प की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन दीपक कुमार कानौजिया	91-94
५	वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल के ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन संतोष कुमार वर्मा	95-99
५	कम्पनी शैली : उद्भव, विकास और अन्त शिखा पाण्डेय	100-104
५	द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर तृतीय विश्व और गुट निरपेक्ष आंदोलन चन्दन कुमार	105-110
५	आधुनिकीकरण का प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर डॉ० प्रतिमा सिंह	111-112
५	उच्च माध्यमिक स्तर के कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन आलोक कुमार एवं प्रो० मुदित राठौड़	113-119
५	पर्यावरण जागरूकता के विकास में शिक्षा की भूमिका एवं पर्यावरण असंतुलन : एक चुनौती डॉ० हरविन्द्र सिंह	120-122
५	डॉ० राममनोहर लोहिया के ट्रस्टीशिप (पूँजीवाद) सम्बन्धी विचार डॉ० समरेन्द्र बहादुर सिंह	123-128
५	भारतशतकम् खण्डकाव्य में राष्ट्रीय चेतना सूरज कुमार सरोज एवं डॉ० अखिलेश कुमार	129-132
५	उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण सूत्रों की सीखने की दृष्टि से उपयोगिता सौरभ बाबू दुबे एवं डॉ० अनुपमा वर्मा	133-135
५	अद्वैतवेदान्ते विवेकानन्दस्य योगदानम् लालु-दे	136-138
५	आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये नाटकस्य महत्वम् रामनिरी मीना	139-142
५	जातकों में वर्णित रामकथा आख्यान का निहितार्थ मुकेश कुमार यादव	143-146

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में चीन की संतुलनकारी भूमिका में क्वाड

शिवम सिंह

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर
डॉ० जयकुमार मिश्र (शोध निर्देशक)

प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र या इंडो-पैसिफिक रीजन (आईपीआर) एक ऐसा भू-राजनीतिक क्षेत्र है, जो हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर के दो क्षेत्रों तक फैला हुआ है। विशाल हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर के सीधे जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को 'इंडो-पैसिफिक' देश कहा जाता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। चीन के उदय व उसकी विस्तारवादी नीतियों के कारण हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केन्द्र बनता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध एवं तकनीकी प्रतिस्पर्धा के कारण पिछले कुछ वर्षों से यह जलीय भू-भाग दोनों महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का एक नया केन्द्र बन कर उभर रहा है।

चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद या क्यूएसडी का उद्भव प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन आक्रामकता के विरुद्ध फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के तिहरे समझौते की याद दिलाता है। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में सत्ता संघर्ष का जो खेल चल रहा है, उसमें नए खिलाड़ी का उद्भव अनिवार्य हो गया है। क्योंकि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के स्थायित्व के लिए चीन चारों ही देशों की एक साझा परेशानी बना हुआ है। इसीलिए क्वाड का उद्भव इस क्षेत्र में चीन से निपटने के रूप में देखा जा रहा है। अति महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्रीय विस्तार करके सुपर पावर का दर्जा प्राप्त करना चीन की प्रत्यक्ष इच्छा रही है। वह इसे कूटनीति तथा रक्षा, दोनों ही तरह से दूरदर्शी अंदाज में सोचता है। क्योंकि चीन आर्थिक रूप से उच्चता के शिखर पर है, इसलिए वह अब पूरे विश्व में अपनी मजबूत पकड़ बना कर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। लेकिन उसकी समस्या उसकी भौगोलिक स्थिति और स्ट्रेट ऑफ मलक्का (मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के इंडोनेशियन द्वीप के मध्य जल पट्टी पर) निर्भर है।¹

क्वाड के रणनीतिक महत्व को चीन के आक्रामक राजनीतिक कार्यकलाप के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। चूंकि यह क्षेत्र भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से गुजर रहा है, सभी चारो देश दक्षिणी चीन सागर और हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को लेकर सतर्क हैं। चार लोकतांत्रिक देशों की यह नई धुरी एक व्यवहारिक सहभागिता तैयार करने के लिए सामने आई है, ताकि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में चीन से निपटा जा सके। मतलब क्वाड का गठन समान विचारों वाले लोगों की पहल है जो समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान के समान उद्देश्य से साथ आए हैं। इसमें सभी का साझा हित शामिल है ताकि आपसी तालमेल से इसे मजबूत करके एशिया के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। सहभागिता का मुख्य जोर परिस्थितियों से निपटने की व्यवस्था करना है।

एशिया में अपने मित्र देशों की तरह जो चीन की आक्रामक मुद्रा के बारे में चिंतित हैं भारत भी उसका शिकार रहा है। चीन ने भारत के साथ लंबे समय से चली आ रहे सीमा विवाद को लंबे समय तक जीवित रखना चाहता है। इन वर्षों में चीन अपने दावों को साबित करने के लिए इतिहास के तथ्यों में भी तोड़ मरोड़ कर रहा है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। सीमा निपटान के मुद्दे के अलावा, वहां दोनों देशों के बीच कई गैर जरूरी मुद्दे हैं जिन्हें चीन बनाए रखना चाहता है। भारत-प्रशान्त क्षेत्र में अपने भागीदारों के साथ जुड़ना भारत के लिए एक जरूरत है, विशेष रूप से 2020 गलवान घाटी संघर्ष के बाद, चीन भारत संबंधों में मुश्किल दौर आया। भारत अब मुद्दा आधारित साझेदारी में विश्वास करता है, और यह भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान, भारत-अमेरिका-जापान, भारत-आस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया जैसे कई मंचों पर भारत की साझेदारी को बताता है, जो हाल के दिनों में तेजी से बढ़े हैं। तेजी से महाशक्ति बनते और आक्रामक होते चीन का सामना करते हुए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा जापान के साथ-साथ आसियान जैसे देश अपनी चीन संबंधी नीतियों पर पुनर्विचार तथा पुनर्मुल्यांकन कर रहे हैं।²

भारत, अपने क्वाड साझेदारों के साथ, हिन्द-प्रशान्त में अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है। सितंबर 2019 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्वाड ने महत्वपूर्ण रूप से खुद को आगे बढ़ाया है। भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के मकसद से और अंततः हिन्द-प्रशान्त में एक

मजबूत, टिकाऊ, संतुलित तथा समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से अप्रैल 2021 में एक आपूर्ति श्रृंखला पहल की शुरुआत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भारत, अमेरिका तथा जापान के साथ 2020 से मालाबार अभ्यास में भाग लेना शुरू किया। इस क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को इसकी "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" को बढ़ावा देने से भी समझा जा सकता है, जिसमें दक्षिणपूर्व एशिया के साथ आर्थिक जुड़ाव तथा पूर्वी एशिया (जापान, कोरिया गणराज्य), ऑस्ट्रेलिया, तथा न्यूजीलैंड के साथ-साथ प्रशान्त क्षेत्र के द्वीप देशों के लिए रणनीतिक सहयोग की बात कही गई है। अमेरिका-जापान के साझे बयान में भी कहा गया है कि हम दुनिया के फायदे के लिए हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में अन्य पक्षों के साथ भी साझेदारी करेंगे। अमेरिका तथा जापान के साझा बयान से स्पष्ट है कि क्वाड की सफलता के लिए भारत के साथ साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण है।

जी-20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बार फिर क्वाड संगठन के प्रति अपने-अपने देश की न सिर्फ प्रतिबद्धता जताई है बल्कि सीधे तौर पर चीन को यह संदेश भी दिया है कि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में शांति के लिए उसकी गतिविधियों पर इस संगठन के जरिए नजर रखी जाएगी। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडन की यह पहली भारत यात्रा थी। क्वाड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा जापान का संगठन है जो वर्ष 2017 के बाद तेजी से आकार ले रहा है। इन देशों का कहना है कि क्वाड का उद्देश्य हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र को खुला, शांतिपूर्ण तथा सभी के सामान्य अवसर वाला बनाना है। हालांकि, चीन और रूस क्वाड को अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया में शीत युद्ध काल को दोहराने वाला संगठन करार देते हैं।³ क्वाड नेताओं की मई, 2023 में जापान में बैठक हुई थी जिसमें क्वाड के तहत मौजूदा वैश्व आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था की जगह एक दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने पर बात हुई थी। मोदी और बाइडन के बीच मुलाकात में भी यह मुद्दा उठा। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला को विश्वस्त बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस संबंध में अमेरिकी कंपनियों की तरफ से भारत में निवेश करने के फैसले का स्वागत किया गया है। अत्याधुनिक उद्योगों के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों पर दोनों नेताओं ने संतोष जताया।

18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हिन्द-प्रशान्त में शांति, सुरक्षा तथा समृद्धि में ही हम सबका हित है। आज की जरूरत है कि एक ऐसा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र बने जहां समुद्र पर कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समझौते (यूएनसीएलओएस-यूएन कंवेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी) समेत दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानून समान रूप से लागू हों। जहां नौवहन व उड़ानों की स्वतंत्रता हो और जहां सभी के फायदे के लिए बेरोकटोक कानून सम्मत कारोबार हो। भारत का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावकारी हो तथा इसमें उन देशों के हितों का भी ध्यान रखा जाए जो चर्चाओं का हिस्सा नहीं हैं। भू-राजनीतिक संघर्षों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि, 'आज का युग युद्ध का नहीं है' और वार्ता व कूटनीति से ही संघर्षों का समाधान किया जा सकता है। इस सम्मेलन में भारत, चीन के अलावा आसियान के सभी देशों तथा रूस, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में आसियान देशों के दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करता है, साथ ही एक मुक्त हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र को सभी के हितों के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत तथा आसियान के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया जिसमें कनेक्टिविटी, व्यापार, डिजिटल बदलाव जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 12 सूत्रीय प्रस्ताव में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, आतंकी फंडिंग और साइबर दुस्प्रचार के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई का आह्वान करने के साथ-साथ बहुपक्षीय मंच पर वैश्व दक्षिण की आवाज उठाने की बात भी कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा इतिहास तथा भूगोल भारत व आसियान को जोड़ता है। साझा मूल्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि तथा बहुध्रुवीय दुनिया में साझा विश्वास भी हमें एक साथ बांधता है। आसियान भारत की हिन्द-प्रशान्त पहल में एक प्रमुख स्थान रखता है।⁴

चीन के बढ़ते बर्चस्व और भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षा से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए न केवल अमेरिका बल्कि जापान, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के लिए अलग-अलग तरह की रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। जर्मनी ने 'हिन्द-प्रशान्त के लिए दिशा निर्देश नीति' तैयार की है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ ने 'हिन्द-प्रशान्त सहयोग के लिए रणनीति' की घोषणा की है।

अमेरिकी-चीन प्रतिद्वंद्विता के कारण इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों और चीन के बीच हथियारों की होड़ बढ़ने लगी है। हाल के वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर तथा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का काम किया है। उस पर दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करने के आरोप भी लगे हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर चीन की इस विस्तारवादी मानसिकता पर लगाम लगाना चाहता है। जलीय क्षेत्र में 'महाशक्तियों' की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण प्रतिस्पर्धि राष्ट्रों का सैन्य खर्च बढ़ गया है। जलीय क्षेत्र में होने वाला यह बदलाव पूरी दुनिया को अस्थिर कर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका इंडो-पैसिफिक रिजन में प्रवासी शक्ति रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए इसे अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है, जिसे अब चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है।

इस सामरिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए अमेरिका विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। फरवरी 2023 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडो-पैसिफिक में बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए 25 अरब अमेरिकी डॉलर के एक फंड निर्माण की घोषणा की है। इस फंड का एक बड़ा हिस्सा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर खर्च किए जाने की योजना है। बाइडेन की इस योजना का मकसद चीन को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने तथा हिन्द-प्रशान्त में अमेरिकी भूमिका को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।⁵ चीन और अमेरिका की इस सामरिक प्रतिस्पर्धा के कारण अक्सर इस क्षेत्र में तनाव के बिन्दु उभरते रहते हैं। महाशक्तियों की इस प्रतिस्पर्धा के कारण इस क्षेत्र में अन्य देशों के संबंध भी व्यापार तथा वाणिज्य के मोर्चे पर प्रभावित हो रहे हैं। अगर प्रतिस्पर्धा का यह सिलसिला किसी बड़े सैन्य संघर्ष में बदलता है तो इसका सीधा असर वैश्विक सप्लाय चैन तथा ब्लू इकॉनामी पर पड़ेगा। ऐसे में चीन को इस क्षेत्र से दूर करने के अमेरिकी प्रयास अगर कारगर साबित नहीं हो पाते हैं, तो हिन्द-प्रशान्त तथा उससे जुड़े देशों के लिए चीन की चुनौती आगे भी जारी रहने वाली है।

2017 में जब क्वाड को मजबूत करने पर सहमति जताई गई थी, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थे, जो अभी भी भारत की अगुवाई कर रहे हैं। भारत को छोड़कर बाकी तीनों देशों के राष्ट्र प्रमुख अब बदल चुके हैं। इस राजनीतिक स्थिरता के पहलू पर भी क्वाड के बाकी सदस्यों की नजर है। बीते तीन सालों में जिस जिस तरह से सीमा विवाद पर भारत ने चीन के उकसावे की हर कार्रवाई का झुठोड़ जवाब दिया है, उससे भी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत नजर आ रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान भी इस बात को स्वीकार करते हैं। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र का सिर्फ सैन्य नजरिए से ही महत्व नहीं है, इसका आर्थिक पहलू उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वाड सदस्य के तौर पर भारत इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है, जिससे जापान, अमेरिका और बाकी देशों का चीन के मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता कम हो जाता है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के व्यापारिक दबदबे का मुकाबला करने में भारतीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। चीन के हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में विस्तारवादी मंसूबे से अमेरिका, जापान को सबसे ज्यादा नुकसान है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लिए सामरिक नजरिए से इस क्षेत्र का बहुत महत्व है। इस क्षेत्र से भारत अच्छे तरीके से परिचित है। इन क्षेत्रों में भारत की स्थानीय जानकारी और खुफिया पहुंच किसी भी तरह से चीन से कम नहीं है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान मुक्त और खुले हिन्द-प्रशान्त के पक्षधर हैं। इन देशों की मंशा है कि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में शांति कायम रहे, ताकि इस क्षेत्र से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई बाधा नहीं आए। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान समेत कई देशों के साझा हित जुड़े हुए हैं।

चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते ही ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान तथा अमेरिका का क्वाड गठबंधन मजबूती से जोर पकड़ रहा है। क्योंकि अमेरिकी प्रभुत्व अब कमजोर पड़ रहा है तो अमेरिका को अब अपने साथियों संग मिलकर अपनी पकड़ ठोस बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। एक खुले तथा स्वतंत्र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के लिए क्वाड अमेरिकी रणनीति के केन्द्र में है। ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन के साथ 'ऑक्स' जैसी पहल के बावजूद अमेरिका के लिए क्वाड की अहमियत जरा भी कम नहीं हुई है। स्पष्ट है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, तथा जापान को साथ लिए बिना अमेरिका एशिया में स्थायित्वपूर्ण शक्ति संतुलन नहीं बना सकता। अमेरिका इस बात को भलीभांति समझता है। यही कारण है कि जहां लंबे समय तक क्वाड की कोई बैठक नहीं हुई, वहीं जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद क्वाड नेताओं की बैठकें लगातार आयोजित हो रही हैं, फिर भी इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि क्वाड की राह में अभी भी तमाम प्रकार की चुनौतियां बनी हुई हैं। सदस्य देशों को उनका समाधान कर इस संगठन को तार्किक बनाने के लिए सक्रिय रहना होगा।⁶

क्वाड के जरिए सदस्य देश यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का उपयोग नौवहन की स्वतंत्रता तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे मूल सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किया जाए। क्वाड का मुख्य उद्देश्य चीन के लोकतंत्र विरोधी रवैये से हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना है। दूसरी तरफ चीन क्वाड की कड़ी आलोचना करता रहता है। वह क्वाड को विचारधारा पर आधारित गुट बताते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए हानिकारक बताता है। उसका कहना है कि अगर क्वाड अपने विरोधात्मक पूर्वाग्रह तथा शीतयुद्ध की मानसिकता से बाहर नहीं निकलता है तो वह अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा।

संदर्भ सूची :

1. चहार प्रेरणा, चतुष्कोणीय प्रवाह में ज्वार: एशियाई व्यवस्था का नया उभार, वर्ल्ड फोकस, भारतीय-प्रशान्त क्षेत्र में उभरते आयाम, वैश्विक शक्तियों की भूमिका, मार्च, 2018, पृ०-94
2. साहा प्रमेशा, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र की उभरती गतिशीलता में भारत की भूमिका, 7 फरवरी, 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.orfonline.org/hindi/research/indias-role-in-the-emerging-dynamics-of-the-indo-pacific/>
3. हिन्द-प्रशान्त में शांति के लिए क्वाड जरूरी, दैनिक जागरण, वाराणसी, 9 सितंबर, 2023, पृ०-1
4. दक्षिण चीन सागर में हमारे भी हित, दैनिक जागरण, वाराणसी, 8 सितंबर, 2023, पृ०-1
5. डॉ० सोमानी एन. के. और डॉ० शर्मा नीलम, इंडो-पैसिफिक में चीन का बढ़ता वर्चस्व और अमेरिकी चुनौती, वर्ल्ड फोकस, अमेरिका-चीन संबंध, अप्रैल 2023, पृ०-67
6. चेलानी ब्रह्मा, क्वाड के समक्ष लक्ष्य साधने की चुनौती, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र से जुड़े मुद्दों से निपटने पर हो ध्यान केन्द्रित, <https://www.google.com/amp/s/www.jagran.com/lite/editorial/apnibaar-quad-a-strategic-alliance-of-major-democracies-of-the-indo-pacific-region-is-now-becoming-more-of-a-reality-than-concept-22793765.html>

